6. Shri Vijay Goel, Minister of State in the Prime Minister's Office;
7. Shri Ravi Shankar Prasad, Minister of State in the Ministry of Coal and Mines;
8. Shri Rajiv Pratap Rudi, Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry; and
9. Shri Ashok Pradhan, Minister of State in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आर्थिक मंदी

*21. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मौजूदा आर्थिक मंदी का कारण इस स्थिति का उपशमन करने के लिए किसी ठोस आर्थिक नीति का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं से निपटने के लिए अथवा इनका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या वर्तमान स्थिति का समाधान करने के लिए सरकार पर पूंजीगत व्यय बढ़ाने हेतु दबाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटिल): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से, वर्ष 2001-02 के बजट में निहित नीति में कृषि क्षेत्र के सुधारों की गति तेज करने और खाद्य अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंध, संरचनात्मक निवेश में तेजी लाने, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार में सुधार जारी रखने, आर्थिक गतिविधियों में बाधा डालने वाले शेष नियंत्रणों को हटा कर संरचनात्मक सुधारों को और आगे बढ़ाने, बेहतर शैक्षिक सुविधाओं तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से मानव विकास, गैर-उत्पादक व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, निजीकरण की प्रक्रिया और सार्वजनिक उद्यमों की पुनर्संरचना की गति को तेज करने तथा कर आधार को व्यापक बना कर राजस्व में वृद्धि करने और निष्पक्ष तथा न्यायसंगत कर-व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही स्वदेशी मांग को बढ़ाने के लिए उपाय किए गए

हैं। इन उपायों में, अन्य के साथ-साथ, संविदात्मक बचतों पर ब्याज दरों में कटौती, निगमित और गैर-निगमित क्षेत्रों द्वारा अदा किए जाने वाले उपकर को समाप्त करके करों में कटौती, सर्वोच्च सीमाशुल्क दर में और कमी करना, उत्पाद कर प्रणाली को बहुत सरल बनाना, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बृहत-आर्थिक तथा मौद्रिक गतिविधियों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर को 7 प्रतिशत से घटा कर 6.5 प्रतिशत कर दिया है तथा बैंकिंग प्रणाली के लिए नकदी आरक्षित अनुपात में कमी भी करके उसे युक्तिसंगत बना दिया है। आशा है कि बजट नीति की पृष्ठ भूमि में मांग को बढ़ाने के लिए किए गए इन विशिष्ट उपायों द्वारा विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 2001-02 के बजट में अति महत्वपूर्ण संरचनात्मक क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय को बढ़ाने की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। इन क्षेत्रों में बजटीय परिव्ययों के उपयोग पर बारीकी से नजर रखी जा रही है ताकि परिव्यय के उपयोग तथा परियोजनाओं को तीव्रता से पूरा करने को सुनिश्चित किया जा सके।

Economic Slump

†*21. SHRI JANESHWAR MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the present economic slow-down is due to absence of any concrete economic policy to alleviate this situation;

(b) if so, what steps have been taken to cope up/solve these problems;

(c) whether Government are being pressed to increase the capital expenditure to tide over the present situation; and

(d) if so the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL): (a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir.

(b) to (d) with a view to promoting growth, the broad strategy enunciated in the Budget for 2001-02 has emphasised speeding up of agricultural sector reforms and better management of the food economy; intensification of infrastructure investment, continued reform in the financial sector and capital markets, and deepening of structural reforms through removal of remaining

†Original notice of the question was received in Hindi.

controls constraining economic activity; human development through better educational opportunities and programmes of social security; stringent expenditure control of non-productive expenditure; acceleration of the privatisation process and restructuring of public enterprises and revenue enhancement through widening of the tax base and administration of a fair and equitable tax regime. Besides, mesures have been taken to stimulate domestic demand. These among others include reduction in interest rates on contractual savings, tax cuts thorugh abolition of surcharge payable by corporates and non-corporates, further scaling, down to peak customs tariff, major simplification in the excise duty regime etc. Further, Reserve Bank of India on the basis of a review of macro-economic and monetary developments, reduced the bank rate from 7 per cent to 6.5 per cent and also effected reduction and rationalisation in the Cash Reserve Ratio for the banking system. These specific measures to stimulate demand in the backdrop of Budget strategy are expected to have a favourable impact on growth. The Budget for 2001-2002 has already provided enhanced central plan outlays for key infrastructure sectors. The utilisation of budgeted outlays in these areas are being closely minitored to ensure speedy utilisation and completion of projects.

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय। मैंने मंत्री जी का बयान पढ़ा और मेरे पहले सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि देश में कोई भी आर्थिक मंदी नहीं है। मैं इस सरकार के बारे में क्या कहूं, इस सरकार को गर्दिश में भी हरियाली दिखाई देती है। इस समय देश के करीब 75 करोड़ किसानों की खरीददारी की ताकत मर चुकी है, सरकार की औद्योगिक नीति के कारण जिन मजदूरों की छंटनी हो रही है उनकी क्रय-शक्ति भी समाप्त हो चुकी है और बाजार बहुत मंदा है लेकिन लगता है कि यह सरकार कभी बाजार में जाती नहीं, अपने दफ्तर में बैठी रहती है और अपने अफसरों से सलाह लेकर जवाब दे देती है। तो एक तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार हकीकत को समझने की कोशिश करे और फिर मेरा कहना है कि अगर आर्थिक मंदी नहीं है तो मेरे बाकी सवालों का जवाब क्यों दिया गया कि ये-ये हालत सुधारने के प्रयास हो रहे हैं। यह एक तरह से अंतर्विरोध की बात है क्योंकि अगर देश खुशहाल है तो हालत सुधारने की क्या बात है। खुशहाली की हालत सुधारने के लिए या आर्थिक मंदी का मुकाबला करने के लिए जो जवाब दिया गया, मैं समझता हूं कि वह नहीं दिया जाना चाहिए था, सब सवालों के लिए एक जवाब कह देते कि देश बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नया काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों ने बाद में सफाई देने की कोशिश की है।

सभापति जी, मैंने वित्त मंत्री जी का एक बार बयान पढ़ा था कि जिन लोगों पर 45,000 रुपए से नीचे कर्जा है, अगर वे मूल धन दे दें तो उनके कर्जे की राशि माफ कर दी जाएगी। यह बड़े उद्योगों और व्यापारियों के लिए था। मैं एक सवाल यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह किसानों के लिए

भी लागू होगा या केवल व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए ही लागू होगा? इसी के साथ लगा हुआ मेरा एक और सवाल है कि इस समय हमारे देश का बकाया राजकोषीय ब्यौरा क्या है मौजूदा हालत में, इससे मालूम पड़ जाएगा कि आर्थिक तंगी है या नहीं और कुल बकाया का कितने प्रतिशत देश के पूंजीपतियों पर है और इसे हासिल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? मैं समझता हूं कि क्योंकि यह सवाल बहुत गंभीर है, पूरा देश कराह रहा है, इसलिए रहना तो वित्त मंत्री जी को चाहिए था, लेकिन ठीक है, कोई भी मंत्री रहे, वह जो भी जवाब देंगे, वह सरकार का जवाब माना जाएगा लेकिन हम चाहेंगे कि इस पर मंत्री जी जरा सफाई से जवाब दें।

श्री बालासाहेब विखे पाटील: सभापति महोदय, स्लो-डाऊन सभी जगह है, यह सबकी मान्यता है और हम यह मान रहे हैं कि स्लो-डाऊन तो है लेकिन इससे बाहर आने के लिए सरकार की जो कोशिशें हैं उनमें तो मैं नहीं जाऊंगा लेकिन माननीय सदस्य ने जो सवाल किए हैं वे खासकर NPA के बारे में किए हैं। इस सवाल से जुड़ा नहीं है, तो भी मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने 25,000 रुपए प्रिंसिपल लिया है, उसके ऊपर ब्याज माफ करके ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल एमाउन्ट रिकवर करने के लिए कोशिश की जा रही है। RBI ने भी इसके लिए गाईडलाईंस दी हैं और सभी बैंकों को भी कहा गया है और यह सभी वर्गों के लिए लागू है चाहे वह पूंजीपति हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह व्यापारी हो, सबके लिए यह सहूलियत है, उसमें हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। जहां तक आपने बकाया राशि की बात कही है, यह बात सही है कि स्थिति गंभीर है, वह absolute term में बढ़ गया है लेकिन नैटNPA कम हो गया है, इससे काम नहीं चलेगा सरकार भी इस बारे में चिंतित है कि NPA कैसे कम हो जाए क्योंकि कम से कम 63,000 करोड़ रुपया या सभी फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशंस को मिलाकर कम से कम 80,000 करोड़ रुपया उसमें लगा हुआ है। इसमें कट-ऑफ डेट हमने 1998 रखी है जिसको 25,000 हम कहते हैं, उस बकाया के कारण जो wilful defaulter हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज दर्ज किए गए हैं और हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग जेल भी जा सकते हैं। इसमें बड़ा या छोटा, अमीर या गरीब या कारपोरेट सैक्टर, ऐसा कोई भेदभाव हम नहीं करते हैं और न किया है। कई केसेज अभी जो जून तक हमने OTS के दिए थे, सितंबर के आखिर तक उनका प्रपोजल तय करना था। मेरे ख्याल से जितने केसेज आ गए हैं, वे सब हमने तय किए हैं और बाकी सभी केसेज DRT में चले गए हैं। यह सवाल स्लो-डाउन के हिसाब से होते हुए भी माननीय सदस्य ने जो अन्य सवाल पूछे हैं। मैंने उनका जवाब दिया है।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, मेरा ख्याल है कि इस सरकार के घटक दलों में भाजपा एक मुख्य पार्टी है। इसके आर्थिक मामलों के प्रकोष्ठ के एक संयोजक हैं प्रोफेसर जय दुबासी। उन्होंने बयान दिया है कि इस सरकार के पास कोई आर्थिक समझ नहीं है। चूंकि यह वित्त मंत्रालय से संबंधित सवाल है, इसलिए शायद उनके बयान की कटिंग मंत्री जी के सामने अवश्य आई होगी। उन्होंने कहा है कि सब कुछ तो ये दूसरे देशों के सामने गिरवी रखने जा रहे हैं यहां तक कि बैंकिंग और इंश्योरेंस भी।

महोदय, मैं देश की मौजूदा हालत के बारे में लंबी बहस नहीं करूंगा लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि वे उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, वे आर्थिक मामलों के संयोजक हैं, उन्होंने यह कह दिया कि आपके पास कोई आर्थिक समझदारी नहीं रह गई है और इस दयनीय स्थिति को देखते हुए हम जिस तरह से WTO के चक्कर में फंस गए हैं, उससे लगता है कि देश गुलाम हो जाएगा क्योंकि चीन ने भी उस पर दस्तखत कर दिए हैं, उसका सामान बड़े सस्ते भाव पर यहां आ जाता है और इससे हमारे यहां तैयार किए हुए सामान के छोटे-छोटे कारखाने चौपट हो जायंगे। महोदय, WTO की एक धारा है कि कोई भी देश यदि चाहे तो वह 6 महीने का नोटिस देकर उससे हट सकता है। क्या हम में यह हिम्मत है कि हम उससे हट जाएं और आर्थिक गुलामी से बचने के लिए एक मजबूत झटका दिया जा सके?

विदेश मंत्री श्री जसवन्त सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक ही प्रश्न की परिधि में कई प्रश्न पूछे हैं। इसका जो अंतिम आशय है WTO को लेकर, उससे मैं आरंभ करता हूं। वैसे वित्त मंत्रालय से WTO का सीधा कोई संबध नहीं है। वैसे WTO पर यहां चर्चा भी होगी। अभी दोहा में WTO पर जो बैठक हुई, उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या निर्णय लिए गए, मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य देंगे और माननीय सदस्यों को उस वक्त इस पर पूरी चर्चा करने का अवसर मिलेगा और WTO से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को उठाने का समुचित अवसर उन्हें मिलेगा। यह तो उसका एक पहलू है।

दूसरा, मैं माननीय सदस्य को बतादूं कि नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस जिस नीति पर काम कर रहा है वह किसी एक घटक दल की नीति नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी की नीति पर नहीं है, नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस का चुनावों से पहले एक संयुक्त रूप से इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो के तहत हम काम कर रहे हैं, किसी एक पार्टी की नीति के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं। तीसरे, माननीय सदस्य ने कहा कि कोई एक महानुभाव हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी के इकोनोमिक सेल में थे। अब हैं या नहीं हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। उनका कोई वक्तव्य है। यह तो संभव नहीं है कि हर वक्तव्य को लेकर के पूरी चर्चा की जाए और वक्तव्य को ही आधार मानकर नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण किया जाए। मैं माननीय सदस्य को कहूंगा तथा आश्वासन देना चाहता हूं कि नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस का जो हमारा संयुक्त रूप से मेनिफेस्टो है उसके आधार पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार की टिप्पणियों से हम विचलित नहीं होते हैं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, the hon. Minister, in the later part of his answer, has pointed out two things. One is that there has been a larger outlay in the central plan allocations, and there is a regular monitoring of the Plan expenditure. It has also been pointed out in the same answer that various steps have been taken to stimulate the economy. I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that in the process of monitoring the central Plan expenditure, it has been found that most of the public sector enterprises are

able to spend the budgetary support allocated to them. The other component of the Plan outlay is the internal resources and extra budgetary resources, IEBR. Most of the Central public sector enterprises have failed to mobilise the committed IEBR. I want to know whether it is a fact and whether it has been revealed in the course of monitoring the Central Plan expenditure.

Sir, in this connection. I would also like to know from the hon. Minister— as he has pointed out that various steps have been taken to stimulate the economy- —more than six months of the current financial year are over— about the latest assessment of the Finance Ministry in regard to the GDP growth for the current year. I want to know whether it is anywhere near the targeted growth which was projected at the time of the Budget.

SHRI JASWANT SINGH: Sir, the hon. Member has brought out an important aspect of the examination of the total economic situation of the country; and behind this question, is his wealth of experience both as Deputy-Chairman of the Planning Commission as well as Minister of Finance for a considerable number of years. For example, in the last session, we have had a very detailed discussion on the state of the economy, what is being done by way of stimulus that the Government intends to provide, etc. We can have further discussions in this regard.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: We should have one.

SHRI JASWANT SINGH: Certainly.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Thank you.

SHRI JASWANT SINGH: We can have a fuller discussion in this regard because this is a sufficiently important subject for Members to be concerned about, as also for the House to take up, if necessary, more than once in a session; but, certainly, once every session. The Government has no difficulty in discussing this issue. We would be only too happy to do so.

Now, so far as the specific aspects are concerned, whether the public sector enterprises are able to generate sufficient internal resources; they have not.This is a fact; we know it. Why are'nt they able to do it? This is also well known to us. It is not so much as any valued judgement or depiction of any kind of defect on anybody's part.

This is part of the overall deficiency in the economic health that we are currently going through. I assure the hon. Member that it is not as alarming as

one would like to think, because, being a democratic, open, society that we are, the optics gives a picture worse than the reality. The optics of the economic situation of the country conveys a picture of India, as if there is a collapse. There is no collapse. There is inherent vitality and strength in the Indian economy.

So far as the final part of it is concerned, the GDP projection, I do believe that the GDP projections are on line. I have not, at the moment, with me, the exact figures. But, no doubt, you are quite right; we are coming to the end of the third quarter, as it were, of the Budgetary cycle and we should be able to project, with a fair amount of accuracy, in the third quarter, what the GDP projections are. when the House does engage itself in a fuller discussion, we would give you that also.

SHRI J. CHITHARANJAN: Sir, in the reply, the hon. Minister has stated that with a view to promoting growth, a broad strategy was enunciated in the Budget for 2001-02. Towards the end, he has stated, "The specific measures taken on the basis of the strategy to stimulate demand in the backdrop of the Budget strategy are expected to have a favourable impact on the growth." Sir, now, almost six months are going to be over. In this period, if you go through the results of implementation of this strategy, one can very well notice that in all the spheres, the targets are not being attained; there is a slow growth in the industry; the GDP growth is coming down, the tax realisation is coming down; unemployment is increasing; our very valuable public sector undertakings are being sold out; thereby our to achieve a sustained economic growth has been affected. All these things are happening. when you have met with experiences like this, I would like to know, whether the Government has considered as to why it has so happened.

When there is a slowdown in the economic growth, would the Government think of an alternative policy to implement?

SHRI JASWANT SINGH: Sir, the hon. Member has prefaced his question by a number of averments.

SHRI J. CHITHARANJAN: Can it be substantiated by the Government stand?

SHRI JASWANT SINGH: Sir, I am only repeating that which the hon. Member has said. He has prefaced the question by a number of averments and drawn a conclusion. The question was: Would the Government think of an

alternative policy? The Government addresses itself to all the necessary corrections, to whatever is required to be done to stimulate the economic growth of the country. There are other aspects like demand, GDP, etc. What they are has already been discussed. So far as applying the necessary correctives is concerned, the Government is fully mindful of it and is doing that.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, my question has already been put by Shri Chitharanjan. In the last one decade, wrong economic policies are being pursued by various Governments. Would the present Government review the present economic policy which is distracting the progress of this country?

SHRI JASWANT SINGH: Sir, the Government reviews all policies constantly and naturally when hon. Members have voiced their concerns. Even if the hon. Members had not voiced this concern, the Government constantly reviews all policies and their implementation. We will certainly do so.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the recent terrorist attacks on cities of America and the US war against Afghanistan have created an adverse effects on the present economic slowdown of the country.

SHRI JASWANT SINGH: Sir, it is well enough known that September 11 attacks in New York on the World Trade Centre has certainly resulted in the creation of a climate of uncertainty. And not simply in the United States of America but for a time globally. After all, the United States of America is a very large demand centre. This resulted in a concertina effect in East Asia, in South-East Asia and in Europe. But I have noticed, Sir,—though it is not something that I can assert empirically—But I find, Sir, that the nature of the Indian economy being what it is, the size of the Indian economy being what it is, just as at the time of the East Asian crisis or the monetary crisis in East Asia when India was largely protected from that crisis or its full dimensions. In a similar fashion, this time, though not exactly insulated from the global impact of whatever takes place by way of a climate of uncertainty, by and large, the Indian economy has withstood the shock. The factor of uncertainty is there. But I do believe that the shock and uncertainty is now beginning to veer on. The present season, for example, both in India as also now in the Western world and in East Asia, it is the Diwali-Dushara season which is of high consumer spending. Subsequently, the Western world, starting from now roughly going up to Christmas and New Year, it is a very high consumer-spending season. The early indications of this are, the consumer spending is picking up and confidence is beginning to restore.

This is also being reflected in the indices of the stock exchanges. I am not any great expert on stock exchanges but I am informed that the Diwali Mahurat trading on the Bombay Stock Exchange, for example, for the first time in 7 or 8 years—the first three days trading after Diwali, treated as Mahurat trading — has shown a rise of almost 200 to 300 points or something like that. I have not got the exact figures. ...(*Interruptions*)... It is about 100 points. ...(*Interruptions*)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: ट्रेडिंग पर मत जाइए। आपको क्या पता कि कौन सा स्टॉक ऐक्सचेंज कहां क्या कर रहा है? ...(व्यवधान)...

SHRI JASWANT SINGH: I forgot that ...(*Interruptions*)... I agree that ...(*Interruptions*)...

SHRI NILOTPAL BASU: Earlier this Government had stated that the share market index was not ...(*Interruptions*)...

SHRI JASWANT SINGH: I agree ...(*Interruptions*)... I am myself saying that ...(*Interruptions*)... It is one of the indices and it is not the only index. ...(*Interruptions*)... It is not a debating point that I am making in this regard because I am ...(*Interruptions*)...

SHRI NILOTPAL BASU: You are contradicting your own Government policy. ...(*Interruptions*)...

SHRI JASWANT SINGH: I am not contradicting ...(*Interruptions*)... I am not contradicting at all. ...(*Interruptions*)... I am really supplementing the point that there is a rise in confidence. I believe that these are the functions to encourage the restoration of confidence rather than to withdraw from it.

SHRI PREM CHAND GUPTA: Mr. Chairman, Sir, after the Budget of 2001, next day the stock market crashed. A month later the industry started feeling the pinch of recession. Three months later Moody downgraded India's sovereign rating. When the Budget was presented, it was promised that a lot of reforms were in the pipeline. The Minister, in his reply, has stated, "speeding up of agricultural sector reforms." We have seen this and we know how, everyday, our farmers are committing suicide because rice and wheat are not being lifted.

The next point mentioned in the reply is about the better management of the food economy. Sir, Rs. 40,000 crores worth of food has gone waste because there are no storage facilities. The industry is in deep recession. The financial system is in doghouse. And, Mr. Chairman, Sir, 14 per cent of the IDBI's assets

have become NPAs. Sir, IDBI's Rs. 54,744 crores in NPAs as against Rs. 53,033 crores in the previous year. Where are we heading? What are we aiming at? The Government has failed on every front. Saying that stock markets are rising and the economy is in good shape is wrong. They are looting. The financial institutions are being looted in a very systematic manner. The example of UTI is before us. The IDBI has become sick, and nothing is being done in this regard. Then, the industrial houses have taken Rs. 12,000 crores without any justification, and nothing has been done ...*(Interruptions)*... You are mistaken. Mr. Minister, in your reply, you have mentioned about the financial institution reforms. Have you read this? You please read it first, Mr. Minister. It is a part of your reply. So, my supplementary is, what is the Government's long-term planning to come out of the present financial recession? Otherwise, we are heading for a bad time. The hon. Minister may please reply to this question.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Mr. Chairman, Sir, I have already replied about the NPAs situation in the country. Definitely, there is a need for reforms; and a number of measures had already been announced in the Budget. The hon. Leader of the House has rightly mentioned that if there is a general discussion, then all these issues could be covered ...*(Interruptions)*... Kindly hear me.

SHRI PREM CHAND GUPTA: Mr. Chairman, Sir, eight months have passed after placing the Budget on the Table of the House. What is the outcome? Our revenues have come down. Our financial recovery is poor. And he is saying that a lot of measures have been taken to improve the financial condition of the country! What are those measures? Why don't you come out with all the facts? Mr. Chairman, Sir, let us have a discussion on this.

MR. CHAIRMAN: I think we can have a discussion on this.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Yes. Once we have a discussion on this, all the facts will come out ...*(Interruptions)*... We can address these issues in a full discussion.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, why don't they come out with a White Paper on the subject?

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: There is no need to have a White Paper, We may have a full discussion on this. I think, it will be a good thing to have a discussion ...*(Interruptions)*...

SHRI PREM CHAND GUPTA: But you should reply to what has been raised here, you should come out with a proper planning. What are your plans? ...*(Interruptions)*...

श्री रामदास अग्रवाल: सभापति महोदय, यह एक सर्वविदित विवादास्पद फैक्ट है, किन्हीं कारणों से आज विश्व के अनेक विकासशील विकसित, अविकसित देशों में मंदी का दौर है और हम भी उसी का शिकार हैं। ...(व्यवधान)... मैं कहा रहा हूं, आप मुझे बोलने दीजिए ...(व्यवधान)...

SHRI JIBON ROY: Sir, China is maintaining a growth rate of 7.7 per cent.

श्री रामदास अग्रवाल: महोदय, यह विवाद का विषय नहीं है। मंदी का दौर सभी जगह है, कहीं ज्यादा और कहीं कम है। हमारे देश में भी इसका असर है, मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं और मंत्री जी ने भी इन्कार नहीं किया है। इसके उपरांत भी केन्द्र सरकार ने बीच में अनेक कदम उठाए थे ताकि इस मंदी के दौर को रोका जा सके। टैरिफ में कमी करना, बैंक इन्टरेस्ट रेट में कमी करना जैसे कदम उठाए गए जिनका विवरण मंत्री महोदय ने दिया है : मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूं वह बहुत सीधा इसलिए है कि आज बैंकों के पास, हमारे इंस्टीट्यूशन्स के पास बहुत पैसा जमा है। ...(व्यवधान)... आज भी हमारे बैंकों में दस लाख करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट है। ...(व्यवधान)... मंत्री महोदय से मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)... यह तो कोई बात नहीं है। आप मेरे प्रश्न का उत्तर मुझसे ही क्यों मांग रहे हैं, मंत्री जी से मांगिए ...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री रामदास अग्रवाल: मैं प्रश्न कर रहा हूं ...(व्यवधान)... जनेश्वर जी से तो मैं आधे समय में प्रश्न कर लूंगा ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी: आप मंत्री बन गए हैं ...(व्यवधान)...

श्री रामदास अग्रवाल: सभापति जी, मेरा प्रश्न मंत्री जी के ध्यान में आ जाए इसलिए मैं चाहूंगा कि शांति से इस बात को सुनें। यह गंभीर प्रश्न है जो कि केन्द्र सरकार के सामने है, देश के सामने है और प्रश्न यह है कि आज हमारे पास रुपये की उपलब्धता बहुत है। हमारे बैंकों में, इंस्टीट्यूशन्स में बहुत पैसा जमा हो गया है, उन्हें ब्याज देना पड़ रहा है लेकिन उसका सही ढंग से उपयोग कैसे हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट में उसका कैसे उपयोग किया जाए, उत्पादकता में उसका कैसे उपयोग हो, इंडस्ट्री में कैसे उपयोग हो यह प्रश्न हमारे सामने है और इस प्रश्न के उत्तर में मैं जानना चाहूंगा कि क्या उस रुपये का सदुपयोग इस देश की आर्थिक उन्नति में, औद्योगिक उन्नति में, इस देश के रोजगार की उन्नति में किया जा सकता है? क्या इसके लिए इन्होंने कोई विशेष व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है या नहीं किया है? अन्यथा यह रुपया कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन के लोगों के हाथों में चला जाएगा और इन्फ्रास्ट्रक्चर का डेवलेपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे पास जो पैसा बैंकों में, इंस्टीट्यूशन्स में उपलब्ध है उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर में उपयोग करने के लिए क्या उन्होंने कोई विशेष योजना बनाई है?

श्री दीपांकर मुखर्जी: पैसा तो बहुत है प्रोविडेंट फंड में, ग्रेच्युटी में उपलब्ध कीजिए। 1800 करोड़ रुपया है ...(**व्यवधान**)...

श्री बालासाहेब विखे पाटील: यह बिल्कुल सही है कि बैंकों में पैसा जमा है और इसीलिए हमने नेशनल हाईवे डेवलेपमेंट प्रोग्राम्स, रूरल रोड्स पावर प्रोजेक्ट्स, प्रोडिक्टिव रेलवे प्रोजेक्ट्स और एसकेलेटिड लास्ट मंथ कम्पीटीशन प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। प्रोजेक्ट्स में जहां-जहां पैसे की कमी है उसे पूर्ण करने का भारत सरकार ने वायदा किया है और 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा बजट की धनराशि उपलब्ध कराई है। किसी प्रोजेक्ट के विकास के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए नाबार्ड पैसा दे रहा है और पैसे में भी कोई कमी नहीं हो रही है। हम भी यही चाहते हैं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो क्योंकि इसके कारण जी.डी.पी. ग्रोथ बढ़ सकती है और यह मैं पूर्ण विश्वास के साथ दावा कर सकता हूं क्योंकि तीन महीने के अंदर जो रिजल्ट आया है उसमें जी.डी.पी. ग्रोथ बढ़ रही है। सीमेंट है, स्टील है। दो, तीन साल पहले अकाल रहा लेकिन अभी इस साल जो काफी बारिश हुई उसके कारण धान की उपज बढ़ने वाली है और आज पचास हजार करोड़ से ज्यादा धान का गोदाम भरा हुआ है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जो स्थिति स्लो डाउन लग रही है उसमें अगले तीन-चार महीने में उत्पादन बढ़ने की संभावना है। हमारा जी.डी.पी. रेट भी बढ़ेगा इसके लिए हम भी चिंतित हैं। लेकिन यह पेनेकी तैयार करने कि जरूरत नहीं है कि इसके कारण सारा हिन्दुस्तान डूब रहा है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। यह सही नहीं है। सरकार समय-समय पर ध्यान दे रही है और जो कदम उठाना जरूरी है वह उठा रही है।

Release of exploratory location in Contai by ONGC

*22. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether the proposal for release of exploratory location in Contai block was considered by ONGC in REXB meeting on 29th August, 2000;

(b) whether the proposal was purported to release one B category and one A category locations with target depth of 3800 m/trap;

(c) whether as a follow up action 2D seismic data of Contai area was reprocessed;

(d) if so, whether there is any time schedule for taking a decision on release of location; and

(e) if not, the reasons therefor?